यूपी को मिलेंगे 2.44 लाख करोड़ नौकरी और रोजगार के रास्ते खुलेंगे

मोदी @ 3.0

पहला बजट 2024-25

नौजवानों, छात्रों, किसानों और छोटे मझोले उद्यमियों पर विशेष फोकस

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के टैबलेट से इस बार किसानों, युवाओं, महिलाओं और सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए सौगातें निकली हैं। मोदी सरकार 3.0 के आम बजट 2024-25 में किए गए प्रावधानों से यूपी के विकास को रफ्तार मिलना तय है। सीतारमण के भाषण के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बजट को यह विकासोन्मुखी बताया।

यूपी को केंद्र से चालू वित्त वर्ष में 2.44 लाख करोड़ रुपये मिलेंगे। यह अंतरिम बजट से 7482 करोड़ रुपये ज्यादा है। सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं के आधार पर उम्मीद है कि यूपी में करीब 70 लाख नए उद्यम के रास्ते बनेंगे।

एक फरवरी को आए अंतरिम बजट में केंद्रीय करों में यूपी का अंश 218816.84 करोड़ रुपये था, जो अब 223737.23 करोड़ हो गया है। केंद्र की ओर से 50 साल के लिए ब्याज मुक्त लोन के तहत यूपी को पिछले वित्त वर्ष में 17938 करोड़ मिले थे, जो चालू वित्त वर्ष में 20,500 करोड़ रुपये होंगे।

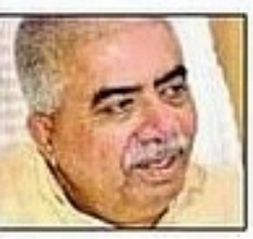

बजट में घोषित 12 में से कम से कम दो औद्योगिक पार्क यूपी में लाए जाएंगे। -राकेश सचान, एमएसएमई, रेशम व खादी मंत्री, यूपी सरकार

कर्ज गारंटी योजना से बनेंगे 22 लाख नए उद्यमी : बजट से यूपी की 20 लाख इकाइयों को संजीवनी मिलेगी। वहीं, एक करोड़ कामगारों को छत मिलेगी। कर्ज गारंटी योजना यूपी के उद्यमियों को राहत देगी। वहीं, करीब 22 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे।

ट्रेड्स योजना सुधारेगी उद्यमियों की माली हालत : यूपी में एमएसएमई सेक्टर में 15,757 करोड़ रुपये एनपीए हो चुके हैं। ट्रेड्स योजना 20 लाख उद्यमियों की माली हालत सुधारेगी। पीपीपी मोड पर आवास बनाने से 10 लाख को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

223737.23

करोड़ रुपये केंद्रीय करों में हो गया उत्तर प्रदेश का अंश

02

लाख युवाओं को इंटर्नशिप योजना से होगा फायदा

40,000

करोड़ हाईवे के लिए

यूपी में हाईवे के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 40 हजार करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। यही नहीं, प्रदेश में करीब दो हजार नए ग्रामीण मार्ग बन सकेंगे।

यूपी में प्राकृतिक खेती को विस्तार

बजट में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया गया है। इससे पूर्वांचल और मध्य यूपी को फायदा मिलेगा। अभी सिर्फ बुंदेलखंड के सात जिलों में प्राकृतिक खेती हो रही है।

100 आईटीआई अपग्रेड होने की आस : केंद्र की ओर से 1000 आईटीआई को हब और स्पोक व्यवस्था में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। इसमें यूपी की 100 आईटीआई को शामिल करने की उम्मीद है।

15 करोड़ लोगों को अगले पांच साल मुफ्त राशन

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि बढ़ाने से यूपी में करीब 15 करोड़ लाभार्थियों को अगले पांच साल तक फायदा मिलता रहेगा।

संकल्प सिद्धि का बजट

बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा, आकांक्षाओं और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। समाज के हर तबके के लिए बजट में किए गए प्रावधान रामराज्य की अवधारणा को साकार करेगा। बजट में अन्नदाता की समृद्धि, कृषि व सहायक क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये और महिला सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे सर्वाधिक लाभ यूपी की आधी आबादी को मिलेगा।
-योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री

24 लाख उद्यमी मुद्रा योजना की सीमा बढ़ाए जाने से होंगे लाभान्वित

मुद्रा योजना की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का फायदा यूपी को मिलेगा। अभी यूपी में 76.79 लाख मुद्रा लोन बांटे गए हैं।

- सीमा बढ़ने से प्रदेश में 24 लाख नए उद्यमी तैयार होंगे। लोन कितना दिया जाए, इसके लिए नया कर्ज आकलन मॉडल लोन की रफ्तार बढ़ाएगा।